

संख्या-3411/11-2008-01(50)/05

देहरादून: दिनांक 29 नवम्बर, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों के निष्पादनार्थ सिंचाई विभाग के निम्नलिखित खण्डों को निम्न प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभाग से सम्बद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क. सं.	लोक निर्माण विभाग द्वारा खण्ड स्थापित किये जाने का स्थान-	सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित खण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	
1.	अल्मोड़ा	यमुना निर्माण खण्ड प्रथम देहरादून।	-
2.	पौड़ी	शक्ति नहर निर्माण खण्ड द्वितीय डाकपत्थर।	-
3.	घम्पावत	सिविल निर्माण खण्ड प्रथम, ढालीपुर।	-
4.	रुदप्रयाग	मनेरी भाली निर्माण खण्ड द्वितीय चिन्यालीसोड़।	-
5.	टिहरी	मनेरी भाली निर्माण खण्ड तृतीय चिन्यालीसोड़।	-

1. सम्बद्ध किये जाने वाले प्रत्येक खण्ड में 01 अधिशासी अभियन्ता (सिविल), 03 सहायक अभियन्ता (सिविल), 02 अवर अभियन्ता (सिविल), 03 लिपिक लेखा सम्बन्धी कार्यों हेतु (खण्डीय लेखाकार हेतु 01 वरिष्ठ लिपिक सम्मिलित करते हुए), 03 लिपिक अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों हेतु (वरिष्ठ लिपिकों को वरीयता प्रार्थनीय है) 01 अमीन एवं 05 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को तैनात किया जाय।

2. सम्बद्धीकरण अवधि में सम्बद्ध खण्ड के कार्मिक पूर्णतः लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में रहेंगे जिसके अन्तर्गत अवकाश स्वीकृति, वार्षिक मूल्यांकन तथा अनुशासनिक/वित्तीय प्रकरणों में निर्णय लेने हेतु लोक निर्माण विभाग में प्रचलित व्यवस्थानुसार लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिकारी सक्षम होंगे, किन्तु वार्षिक मूल्यांकन के अन्तर्गत अपील अथवा बृहद दण्ड जैसे प्रकरण नियोक्ता विभाग अर्थात् सिंचाई विभाग में ही व्यवहृत किये जायेंगे।

3. सम्बद्धीकरण अवधि में सिंचाई विभाग के कार्मिकों की वेतनवृद्धि, प्रोन्नति आदि बिन्दुओं का निस्तारण सिंचाई विभाग के अन्तर्गत ही अपने यहाँ प्रचलित नियमानुसार व्यवहृत किया जायेगा।

4. लोक निर्माण विभाग द्वारा वांछित खण्डों की स्थापना हेतु समबन्धित स्थानों का विवरण मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सि०वि०, को उपलब्ध कराया जायेगा और वे अपने स्तर से कार्मिकों की तैनाती एवं खण्ड के विस्थापन सम्बन्धी सम्यक् आदेश निर्गत करेंगे। फिलहाल कार्मिकों का सम्बद्धीकरण दो वर्ष के लिये किया जायेगा तथा दो वर्ष के बाद की आवश्यकता के सम्बन्ध में दोनों विभागों के मध्य पारस्पर सहमति से यथासमय सम्यक् निर्णय लिये जायेंगे।
5. सम्बद्ध किये जाने वाले खण्डों में तैनात कार्मिकों के वेतन व अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य वित्तीय लाभ सिंचाई विभाग के अधिष्ठान से ही उपलब्ध कराये जायेंगे तथा लोक निर्माण विभाग से सिंचाई विभाग को कोई सैन्टेज चार्ज देय नहीं होंगे।
6. नये सृजित खण्डों हेतु कार्यालय भवन एवं यथा सम्भव आबसीय सुविधा लोक निर्माण विभाग द्वारा करायी जायेगी।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या-3497 / 11-2008-1 / (50) / 05, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निजी सचिव, मा० सिंचाई मंत्री, मा० सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- निजी सचिव, अ० अ० मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 3- आरुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
- 4- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- अपर सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या- 2212 / एम०ओ०१-13 / यू०आर०डी०ए० / 08, दिनांक 29.9.2008 के क्रम में।
- 6- जिलाधिकारी / कौषाधिकारी, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, चम्पावत एवं रुद्रप्रयाग।
- 7- मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या-3107 / मु०अ० / सिंचिउदे / आर-2 / लोनिवि / दिनांक 22.10.2008 के क्रम में।
- 8- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(एस० एस० टोलिया)
अनु सचिव।